



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, २९ सितम्बर, १९९७/७ आश्विन, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ५ जुलाई, १९९७

संख्या एक० आई० एन०-२-सी० (ए०)-एम० एस०/४-३/९६-९३८-१०८७.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, लघु वचन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश में लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'अ' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लघु वचन विभाग, लिपिक (वर्ग-III अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, १९९७ है।

(२) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. निरसन और व्यावृत्तियां.—(१) इस विभाग की अधिसूचना संख्या १-१८/७१-फिन (डब्ल्यू एण्ड एम)-VI तारीख ३१ जनवरी, १९७४ द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ स्मॉल सेविज क्लास III (मिनिस्ट्रीयल) सविमिज रुल्ज, १९७३ का उस विस्तार तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है, जहां तक ये लिपिक के पद को लागू हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

उपबन्ध "अ"

निदेशालय, लघु बचत, हिमाचल प्रदेश में लिपिक (अराजपत्रित) वर्ग-III के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम लिपिक
2. पदों की संख्या 14 (चौदह)
3. वर्गीकरण वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवायें
4. वेतनमान
 - (i) रुपये 950-35-1160-40-1320-45-1500-50-1800.
(मूल प्रवेश वेतनमान 1000/- रुपये के आरम्भ के साथ)। लिपिकों के लिए,—यह वेतनमान रुपये 1200—2130 (वरिष्ठ लिपिक) और रु 1500—2700 (कनिष्ठ सहायकों) के वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों को निकालकर कांडर में कुल पदों को दिया जाना है।
 - (ii) रुपये 1200-40-1320-45-1500-50-2000-60-2060-70-2130.
वरिष्ठ लिपिकों के लिए,—यह वेतनमान लिपिक के रूप में कांडर में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् कांडर में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 40 प्रतिशत को दिया जाना है और इन पदों के पदधारियों को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
 - (iii) रुपये 1500-50-2000-60-2060-70-2550-75-2700.
कनिष्ठ सहायकों के लिए,—यह वेतनमान कांडर में लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के रूप में संयुक्त रूप में न्यूनतम 10 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् कांडर में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 40% को दिया जाना है और इन पदों के पदधारियों को कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
5. नयन पद अथवा अचयन पद अचयन पद
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष:

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गये पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तागीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्वती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणी.—(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिमूचित किए जाते हैं ।

टिप्पणी.—(2) अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य ग्रहंताएं ।

(क) अनिवार्य ग्रहंताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक या 10 जमा 2 की परीक्षा पास हो या इसके समतुल्य योग्यता रखता हो ।

(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखता हो :

परन्तु यह कि भर्ती के लिए टंकण का ज्ञान आवश्यक नहीं होगा, परन्तु चयनित अभ्यर्थियों को उनके अपने अपने विभागों द्वारा विहित टंकण परीक्षा, बिना किसी विस्तार के उसकी नियुक्ति की अवधि से छः मास के भीतर अर्जित करनी होगी। इस प्रकार यदि कोई नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी नियुक्ति के छः मास की अवधि के भीतर टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

- (iii) ऐसे व्यक्ति को टंकण सीखने के लिए छुट्टी अनुवत की जा सकेंगी, यदि वे ऐसे स्थानों में तैनात किये हों जहां टंकण की सुविधायें उपलब्ध न हों।
ऐसी छुट्टी उनकी भविष्य में अनुज्ञेय छुट्टियों में समायोजित की जाएगी।

(ख) वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की लड़कियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं?
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण को दशा में श्रेणियां जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसा कि कालम 11 में विहित किया गया है।

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

- (i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और
(ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

वर्ग-4 कर्मचारियों में से जिन्होंने दसवीं पास की हो या जिन्होंने हिन्दी (रत्न) सहित चयनित अंग्रेजी विषय के साथ दसवीं पास की हो और जिसका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में 31-3-1991 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सहित उक्त नियमित सेवाकाल हो प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु कक्षा मूलक आधार पर इस प्रकार प्रोन्नति या नियुक्त वर्ग-4 के पदधारियों को, जो ऐसी नियुक्ति के समय मैट्रिक (तृतीय श्रेणी) या मैट्रिक (कवल अंग्रेजी) या हिन्दी रत्न की शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, उनकी

वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे सीधी भर्ती के स्तम्भ 7 में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते।

टिप्पणी.—(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी। उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

रन्त उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धों विचार के लिए अपात्र हो जाता वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड ग्रामेड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसक अन्तर्गत वरोयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐकम सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नोकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरोयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी :

परन्तु 31-3-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना?

जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :—

- (क) भारत का नागरिक, या
- (ख) नेपाल की प्रजा, या
- (ग) भूटान की प्रजा, या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगाण्डा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालवा, जेयरे और इथोपिया से, भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों की किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकती।

[Authoritative English text of this Government Notification No. Fin.-2-C (A) SS/4-3/96, dated 5-7-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT (Directorate of Small Savings)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 5th July, 1997

No. Fin.-2 C(A) SS/4-3/96.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk Class-III (Non-Gazetted) in the Directorate of Small Savings, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Small Savings Clerk (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh, Directorate of Small Savings Class-III (Ministerial) Services Rules, 1973, notified vide this Department Notification No. 1-18/71-Fin. (W&M)-VI dated 31st January, 1974 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Clerk.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done, or any action taken under the rule so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

KANWAR SHAMSHER SINGH,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DIRECTORATE OF SMALL SAVINGS, HIMACHAL PRADESH

- | | |
|--|---|
| 1. Name of the post | Clerk |
| 2. Number of posts | 14 (Fourteen) |
| 3. Classification | Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services |
| 4. Scale of pay | <p>(i) Rs. 950-35-1160-40-1320-45-1500-50-1800.
(Basic entry scale with an initial start of Rs. 1000/-).</p> <p>For Clerks.—This scale is to be given to the total number of posts in a cadre minus the posts which are to be placed in the scales of pay of Rs. 1200—2130 (Senior Clerks) and Rs. 1500—2700 (Junior Assistants).</p> <p>(ii) Rs. 1200-40-1320-45-1500-50-2000-60-2060-70-2130.</p> <p>For Senior Clerks.— This scale is to be given to 40% of the total number of posts of Clerks in a cadre after a minimum period of five years as Clerks in the cadre and the incumbents of these posts shall be designated as Senior Clerks.</p> <p>(iii) Rs. 1500-50-2000-60-2060-70-2550-75-2700.</p> <p>For Junior Assistants.—This scale is to be given upto 40% of the total number of posts of Clerks in a cadre after a minimum period of 10 years of service taken together as Clerk and Senior Clerk in the cadre and the incumbents of these posts shall be designated as Junior Assistants.</p> |
| 5. Whether selection post or non-selection post? | Non-selection |
| 6. Age for direct recruitment | Between 18 and 35 years : |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

Note.—(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

(a) *Essential Qualification :*

(i) Should have passed Matriculation with second division or 10+2 Examination or its equivalent from a recognised University/Board.

(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting:

Provided that the knowledge of typewriting shall not be necessary for recruitment but the selected candidates shall have to qualify the typewriting test prescribed by the respective Departments within 6 months of his/her appointment with no extension. Thus, if an appointee fails to qualify the type-writing test within a period of six months of his/her appointment, shall be terminated.

(iii) Leave should be allowed to such persons for learning typewriting if they are posted to places

where typewriting facilities are not available. Such leave would be adjusted against the future leave admissible to them.

(b) *Desirable qualifications :*

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?

Age : No

Educational qualifications : Yes, as prescribed in Column No. 11.

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

90% by direct recruitment and 10% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst the Class-IV officials who have passed Matric or Hindi (Rattan) with Matric (English as one of the subjects) and also possess 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-91) service, if any in the grade:

Provided that the incumbents of the post of Class-IV officials so promoted or appointed on compassionate grounds having the educational qualifications of Matric pass (3rd Division) or Matric (English) only and Hindi Rattan pass at the time of such appointment, shall not be considered to be eligible for their promotion for the post of Senior Assistant until they possess the minimum educational qualifications prescribed for direct recruitment in Column No. 7 above.

Note.—(1) In all cases of promotion, the *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition, that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his

total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex-servicemen* recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex-Servicemen* (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Note.—(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be:—

(a) a citizen of India, or

- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or Other Recruiting Authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.